[श्री मधु लिमये]

इनके विरुद्ध मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं—लेकिन क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर गया है कि वह जो मल्टी स्टेज रॉकेट है—जिसका दूसरा या पहला हिस्सा गिर गया था और जानकार लोगों का अनुमान है कि सिक्यांग से हिन्द महासागर की दिशा में वह छोड़ा गया था—चीन ने प्रक्षेपणास्त्र इस लिये तैयार कर रहा है कि वह भारत और एशियाई लोगों को डराना चाहता है ? इसलिये क्या मंत्री महोदय सदन को इस बात की जानकारी देंगे कि क्या इस वक्त चीन सरकार द्वारा नैपाल पर इतना ज्यादा दबाव डाला गया है कि इसके बारे में वह भारत को और दुनिया को कोई जानकारी न दे ? क्या इस तरह का प्रयास पीकिंग के द्वारा किया जा रहा है ?

SHRI SWARAN SINGH : It is not a fact that we learnt about this only when this call attention notice was admitted. We knew it soon after, sometime towards the end of March ; I cannot at the present moment give the exact date.

About the second question, I have no information that the Nepal authorities did not permit the object to be photographed in Nepal. We must, however, bear this in mind that it will be entirely for the Nepal Government to decide as to whether they would permit anybody to photograph this or not or want information they would liked to give. I would make an appeal to hon. members that we should not discuss it here openly because we should respect the national sovereignty of another country.

श्री मधु लिमये : हम तो जानकारी मांग रहे है, हम उनके अधिकार के बारे में कहां कह रहे हैं ?

SHRI SWARAN SINGH : You cannot compel them to permit us or any other country to photograph this thing. Just as, I have no hesitation in saying, certain parts of multi-stage rockets and in fact material ejected by certain satellites have been discovered even in India and we never permit other countries to photograph them, whether they are friendly or are opposed to us. So each country decides for itself as to what it should do.

श्री मधु लिमये : इसमें दूसरे देशों की बात नहीं है। मैंने यह नहीं कहा है कि हिन्दुस्तान को इजाजत दी गई या नहीं। मैं तो यह जानकारी मांग रहा हूँ कि क्या नेपाल के लोगों को ही उसकी तसवीर खींचने की इजाजत नहीं दी गई। वह हां या न कहें। मैं केवल जानकारी मांग रहा हूँ।

MR. SPEAKER : He got the information by the end of March.

SHRI SWARAN SINGH : About the other question as to whether this was a multi-stage rocket being fired from Sinkiang to the Bay of Bengal, I have already said in the main statement that the material at present available is not conclusive enough to give an opinion one way or the other.

श्री मधु लिमये : मैंने यह पूछा था कि क्या चीन के द्वारा नेपाल पर इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा है जिससे कि इसके बारे में वह गुप्तता रखे। इसके बारे में इनको जानकारी रहनी चाहिये कि चीन के क्या कारनामे चल रहे हैं।

SHRI SWARAN SINGH : I have no information.

12.25 hrs.

RE : MOTION OF PRIVILEGE

MR. SPEAKER : Sometime ago, I made a mention of a privilege motion given notice of by Shri A. B. Vajpayee. But yesterday it was raised by Shri Madhu Limaye—it was not raised rather, it was discussed for nearly an hour and a half.

SHRI NATH PAI (Rajapur) : Not discussed,

MR. SPEAKER: Whatever it is. Whatever language you may use, that was what happened. I wanted to hear the hon. Member and I mentioned that I would allow it to be discussed today. I would like to hear from the hon. Member and then from Government and then take a decision. Inspite of the fact that I had said that I would take it up today, it was raised again at 2 P. M. But having committed myself, I would like now to hear Shri Vajpayee about the privilege motion.

SHRI K. NARAYANA RAO (Bobbili): On a point of order. About the admissibility of the motion.

MR. SPEAKER : I have not admitted anything. I just wanted to hear the hon. Member.

SHRI P. G. SEN (Purnea) : On a point of clarification. What urgency was there for Shri Madhu Limaye to raise this matter and quote from documents yesterday ?

MR. SPEAKER : I myself have regretted it. You have heard me. What else should I do ?

SHRI P. G. SEN : He was quoting so many rules when he was actually violating the rules.

MR. SPEAKER : What does he want me to do ?

As regards Shri Narayana Rao, is he rising to a point of order against Shri Vajpayee getting up ? There is nothing before the House now. I have asked him to explain.

SHRI K NARAYANA RAO : It is not in connection with the privilege motion ? We are seized of the matter. I am rising to a point of order on whether any privilege motion can be raised at all.

MR. SPEAKER : No privilege motion can be raised ?

SHRI K. NARAYANA RAO : In this particular context, this cannot be raised.

MR. SPEAKER : I must hear what the context is. I have not heard him. Whether Shri Madhu Limaye might have said is not relevant to that. I want to hear from Shri Vajpayee what his privilege motion is. Later I may allow it or may not allow it or do anything.

SHRI K. NARAYANA RAO : I agree with you.

MR. SPEAKER : After he explains, he can say whether it is relevant or no.

SHRI K. NARAYANA RAO : Notice of it was given already. We know the subject-matter. A privilege motion has been brought forward on the same subject matter which was disposed of.

If you say my approach is wrong, I am prepared to sit down.

MR. SPEAKER : I thought I should hear him. Then he can argue for half an hour.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव सदन के सामने पेश करके उसकी अनुमति मांगने का मौका दिया है। मैंने प्रस्ताव की सूचना 4 मई को ही दी थी। मैंने मूल प्रस्ताव में गृह-मन्त्री महोदय को शामिल किया था लेकिन आज मैं आपकी अनुमति से अपने मूल प्रस्ताव की परिधि को बढ़ाना चाहता हूं, गृह-मन्त्री के साथ साथ प्रधान मन्त्री और उप-प्रधान मन्त्री को भी इस प्रस्ताव के क्षेत्र के अन्तर्गत लाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि 28 फरवरी को इस सदन में प्रोफेसर बलराज मधोक द्वारा प्रस्तुत सरकार के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। अन्य विषयों के साथ मुख्य चर्चा कच्छ के बारे में हुई थी। कच्छ के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण ने जो निर्णय दिया है उसकी आलोचना की गई थी और उस चर्चा का उत्तर देते हुए, या चर्चा में भाग लेते हुये, प्रधान मन्त्री, उप प्रधान मन्त्री और गृह-मन्त्री ने कुछ वक्तव्य दिये थे। मैं उन वक्तव्यों

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

को विस्तार के साथ सदन के सामने उद्धृत करूंगा लेकिन समय बचाने की दृष्टि से मैं इतना कहना चाहता हूं कि कच्छ के न्यायाधिकरण के निर्णय के परिणामस्वरूप जो भूमि पाकिस्तान को दी जा रही है उसके उपर तीनों मंत्रियों ने अपना खेद प्रकट किया था। गृह मन्त्री ने कहा था कि जो इलाका पाकिस्तान को दिया जा रहा है, में स्वयं उस इलाके में गया था और मैंने देखा था कि हमारे जवानों ने किस बहादुरी से उस इलाके की रक्षा की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि कच्छ के बारे में हमारा मामला एक पक्का मामला था, कास्ट-आइरन केस था, निर्णय हमारे विरुद्ध हो गया हैं, अब उसे मानने के सिवाय हमारे सामने कोई चारा नहीं है। उप प्रधान मन्त्री ने कहा था कि जो भूमि जा रही है उसके जाने पर हम खुश नहीं हैं क्योंकि वह भूमि हमारी थी लेकिन हम वचन से बधे हुये हैं इसलिये हम कच्छ न्यायाधिकरण के निर्णय को चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसी से मिलती जुलती भाषा प्रधान मन्त्री ने भी बोली थी। उस दिन से पहले जब जब इस सदन में कच्छ का मामला आया, चाहे शास्त्री जी के कार्यकाल में हो या उसके बाद, जब जब सरकारी प्रवक्ता बोले, जब जब कच्छ के मामले में सरकारी प्रकाशन हुए, सब में एक ही बात कही गई कि पूरा कच्छ हमारा है, संविधान से, कानून से और परम्परा से लेकिन पाकिस्तान जबर्दस्ती उस पर अधिकार करके हमारे सामने कठिनाई पैदा करना चाहता है। शास्त्री जी ने कहा था कि कच्छ के मामले में कोई भूमि का विवाद नहीं हैं, केवल सीमा तय होनी है और सरकारी प्रवक्ताओं ने भी समय समय पर इसी बात को दोहराया था कि कच्छ की भूमि हमारी है और हमने सारी शक्ति लगाकर उसको बचाने की कोशिश की है।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की हाई कोर्ट में एक नागरिक, श्री शिव कुमार शर्मा द्वारा दायर की गई रिट पेटीशन के जवाब में भारत सरकार की ओर से जो हलफनामा दाखिल किया गया है और उस हलफनामे में जो कुछ कहा गया है, यदि उसे सच माना जाये और मेरे पास उसे सच मानने का कोई कारण नहीं है, तो यह बात स्पष्ट हो गयी है कि प्रधान मन्त्री ने, उप प्रधान मन्त्री ने और गृह मन्त्री ने कच्छ की स्थिति के बारे में, भारतीय संघ में कच्छ के दर्जे के बारे में, संसद को, इस सदन को जान-बूझ कर गुमराह किया है। उन्होंने तथ्यों को छिपाया है, उन्होंने वास्तविकता को प्रकट करने से इनकार किया है और इसलिये वे संसद के, इस सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के दोषी हैं।

कल मेरे मित्र श्री मधु लिमये जी ने सरकार द्वारा दाखिल किये गये हलफ-नामे का एक हिस्सा पढ़ा था मैं उसे दोहराना चाहता हूँ। क्या सरकार को तरफ से, अपने होश हवाश को दुरुस्त रखकर, किसी अदालत में ऐसा हलफ-नामा दाखिल किया जा सकता है ? मगर जो नहीं होना चाहिये था वह किया गया है और इसकी जिम्मेदारी से यह सरकार बच नहीं सकती है। होना तो यह चाहिये था कि ऐसा हलफनामा दाखिल करने के लिये इस सरकार को गद्दी से हटा दिया जाता, यह सदन इस सरकार में अविश्वास प्रकट करता। हम इस सरकार की निन्दा करना चाहते थे लेकिन आपं ने इजाजत नहीं दी इसलिये हमने विशेषाधिका प्रस्ताव लाने का दूसरा मार्ग अपनाया हैं।

शर्मा जी की रिट पेटीशन में कहा गया था कि हमारी भूमि पाकिस्तान को दी जा रही है, यह भूमि का देना बिना कानून बनाये नहीं हो सकता है, इसके लिये संविधान में संशोधन करना जरूरी है, सरकार बिना कानूनी जामा पहने ऐसा काम कर रही है जिसे करने का उसे अधिकार नहीं है। इमानदारी का तकाजा यह था कि सरकार कच्छ के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये सीधे सीधे संविधान में संशोधन करने का विधेयक संसद में लाती लेकिन सर-

कार ने ऐसा नहीं किया। एक पाप पर परदा डालने के लिये अनेक पाप किये जा रहे हैं, एक गलती को छिपाने के लिये देश के हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा किया गया हलफ-नामा भारत को कच्छ में हमला वर साबित कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं उद्धृत करता हूँ

> It is also denied that the territory which the Tribunal has held to lie on the Pakistan side of the alignment of the boundry belonged to Kutch District of Gujrat State under the Bombay Reorganisation Act, 1960 or that it was recognised as Indian territory by the Constitution of India.

जो भूमि हम दे रहे हैं वह हमारी नहीं थी, वह कभी हमारी नहीं थी, इसलिये भूमि देने का सवाल नहीं है। हम उस काले निर्णय को कार्यान्वित कर रहे हैं। क्या प्रधान मन्त्री, उप प्रधान मन्त्री और गृह मंत्री द्वारा इस सदन में दिये गये वक्तव्यों की कोई परवाह नहीं है, क्या यह हलफ-नामा, आज तक के सरकारी प्रवक्ताओं के सारे दावों के खिलाफ नहीं है और क्या यह हलफ-नामा भारत की स्थिति को बिगाड़ने वाला नहीं है ? यही नहीं श्री शिव कुमार शर्मा ने अपनी रिट पेटीशन में प्रधान मंत्री, उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के वक्तव्यों का हवाला दिया था और इस सरकारी एफिडेविट में उनका भी जवाब दिया गया है। जवाब पढ़ने लायक है। उससे इस सदन की आंखे खुलनी चाहिए और इस सरकार की स्थिति के बारे में गम्भीरता से विचार करने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिये। यह विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं और विदेश मन्त्रालय प्रधान मंत्री के अन्तर्गत है। एक के बाद एक वक्तव्य का हवाला देते हुये एफिडेविट में कहा गया है :

> In reply to para 2 of the petition, I say that the statement purported to have been made by the hon'ble Union Home Minister is not material to the issue. It is denied that a very important part of territory or any territory of India is being given to Pakistan and that too for fear of war" A mistaken claim to territory which was in the adverse possession of India does not have the affect of converting such territory into territory of India and demacration of the real boundry does not amount to cession of territory.

यह माना जा रहा है कि जो भूमि हमारी थी वह वास्तव में पाकिस्तान की भूमि थी और हम वहां जबर्दस्ती कब्जा जमाये बैठे थे। एफिडेविट का दूसरा पैरा प्रधान मंत्री, उप प्रधान मन्त्री के वक्तव्यों के बारे में है। मैं फिर उद्धृत करता हूँ :

> The statements purported to have been made by the Prime Minister of India are equally not material to the main issue. It is denied that any part of the territory of India is being given to Pakistan simply on the "false hope of improvement of relations with Pakistan". The statement purported to have been made by the Deputy Prime Minister of India is also not material to the main issue. It is denied that the Union of India has taken any decision to transfer the territory of India which is recognised by Indian Constitution as Indian Territory.

अध्यक्ष महोदय, यह एफेडेविट हैं...

SHRI K. NARAYANA RAO : On a point of order. There is the rule 338 which says that a motion shall not raise a question substantially identical with one on which the House has given a decision in the same session. The other day you were pleased to defer the issue about the motion for future date the date being when the High court decides on a particular thing. In that motion, Sir, the issue involved was this. I will put it in one word. The question involved was whether there was a discrepancy between what the Government of India stated in Parliament and what the Government of India stated in the affidavit in the high court. That was the crux of the issue. The question here also in this privilege motion is similar and identical, the question being once again whether there was a discrepancy between what the Government had stated in the House and also what the affidavit has stated in the

[Shri K. Narayana Rao]

Delhi High Court. This means, the privilege issue cannot be raised now. Now, the discussion on this would be out of order. It should not be allowed further.

MR. SPEAKER : It is so simple now. The affidavit copy, I said, can be laid on the Table of the House. The speeches made by the Minister and opposition members are public properties. They are published. The affidavit and the speeches made are public. They are not secret. It is a public document and it can be in the hands of anybody. After all the speeches made here are public property and the affidavit also. The affidavit also was allowd to be laid on the Table of the House. A comparative study by both can be made. Here is a statement which can be compared. Here is the affidavit filed. How can there be any objection? We are not going into the decision of the court. All right, will you please conclude now?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है उस का मैं स्वागत करता हूं। जो वक्तव्य या भाषण सदन में दिये गये है वह सदन की सम्पत्ति है और उन पर विशेषाधिकार का प्रस्ताव उठाना यह किसी भी सदस्य के अधिकार में है। सरकार यह भी इंकार नहीं करती है कि दिल्ली के हाईकोर्ट में जो हलफनामा दिया गया है उसमें से सही अंश उद्धृत नहीं किये जा रहे हैं। वह पूरा हलफनामा कल टेबुल पर रख दिया गया है। इस सदन को इस बात पर विचार करने का पूरा अधिकार है कि क्या प्रधान मंत्री, उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री ने जान-बूझ कर इस सदन को गुमराह किया है? जो अंश मैंने उद्धृत किये हैं उसके आधार पर यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है कि कच्छ की स्थिति के बारे में और कच्छ के दर्जे के बारे में जो कुछ इस सदन में कहा गया है वह बातें शायद कहने वाले भी ठीक नहीं समझते थे। उनके दिल में कुछ था, उनके मुंह पर कुछ था। उनकी कथनी कुछ रही है और उनकी करनी कुछ और रही है। यह दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार द्वारा दाखिल किये हलफनामें से प्रकट हो गया कि प्रधान मंत्री, उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री यह तीनों इस सदन के विशेषाधिकार के उल्लंघन के दोषी हैं। यह पहला ही मौका नहीं है जब तथ्य को सदन से छिपाया गया हो। अभी उस दिन प्रधान मंत्री महोदया बड़ी नाराज हो गयी जब श्री कंवरलाल गुप्त ने यह आरोप लगाया कि नागालैंड में एक जहाज उतरा है और यह कि प्रधान मंत्री जी जान-बूझ कर इस बात का छिपा रहे हैं तो प्रधान मंत्री बिगड़ गयीं और कहने लगी कि ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिये।

इसी तरह इस सदन के कुछ सदस्य गवाह हैं कि जब चीन ने यकसाईचीन में सड़क बनाई थी तब भी उधर बैठी हुई सरकार ने उस तथ्य को देश से छिपाया था, संसद से छिपाया था और प्रधान मंत्री जी ने इस सदन में वायदा किया था कि ऐसी गलती आयन्दा नहीं होगी लेकिन कच्छ पर जब 1965 में पाकिस्तान ने हमला किया तब भी हमले को तथ्य को छिपाया गया। 1300 गज जमीन पाकिस्तान के कब्जे में जाने की बात को सदन से छिपाया गया था और अब कच्छ के सारे मामले को सदन के सामने लाने से इन्कार किया गया है। असत्य सूचना दी गई हैं, गलत सूचना दी गई है। तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है और जान-बूझ कर सदन को गुमराह किया गया है। इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि आप मुझे अनुमति मांगने की इजाजत दीजिये जिससे यह मामला विशेषाधिकार समिति में जाकर तथ्यों का पता लगाया जा सके और दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। धन्यवाद।

MR. SPEAKER : The law Minister.

SHRI NATHI PAI : We hope you you will hear us also.

MR. SPEAKER : No, please.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है इसलिए मुझे भी आप सुनिये...

MR. SPEAKER : You have already had your say. What is the use now? You would have certainly got your time to speak, but you have already had your say.

श्री मधु लिमये : कल मैंने कुछ नहीं कहा था...

MR. SPEAKER : I will call all of you when it comes for discussion. Now, it is only a question of admissibility. Only one will speak, and then I will have the clarification from the Minister. Later on, I will take my time.

श्री मधु लिमये : कल मैंने केवल इतना ही कहा था इसे जल्दी क्यों लेना चाहिये। इसके बारे में मैं ने साढ़े चार मिनट कहा है और कुछ नहीं कहा है। आप रेकार्ड देख लीजिये।

MR. SPEAKER : I have heard you yesterday. You did explain it in the morning and then in the afternoon. You have had your say. It is unresonable that whenever you want to speak, you must speak, and you necd not have the Chair's permission: No permission was granted to you but then you have had your say. If only you had waited till today, you would have had the opportunity now. But you have already spoken. About an hour and odd was wasted yesterday in the morning and also in the afternoon.

श्री मधु लिमये : मेरा प्रस्ताव बिल्कुल अलग था। आपको क्यों अनुमति देनी चाहिये इस पर मुझे सुनिये। मेरा प्रस्ताव अलग है इसलिए मुझे भी आप को सुनना चाहिए।

MR. SPEAKER : They were right perhaps. When I take a decision, I will give a chance to all of you. Not now, because if I allow you, then naturally, Mr. Mukerjee is also awaiting.

श्री मधु लिमये : मेरा प्रस्ताव अलग है इसलिये मुझे भी सुनना चाहिये। मैं ने केवल साढ़े चार मिनट ही कहा है और वह भी केवल इस पर कि जल्दी क्यों लेना चाहिए। आगे इन्होंने हल्ला किया। मैंने कोई हल्ला नहीं किया था। मैं केवल निवेदन कर रहा था।

MR. SPEAKER : The rule is very clear about it. One of them will explain. Suppose dozen of them give notice, I am not going to give time for all of them.

श्री मधु लिमये : जिन्होंने नोटिस दिया है उनको तो कम से कम सुन लेना चाहिये। मेरा अलग नोटिस है...

MR. SPEAKER : Hundreds of notices may be there. But only one will explain. See the rule and help me. I only want to follow the rule. Only one will explain. When I take a decision and if I admit it, all of you can speak. I have no objection. I only want to follow the rules.

THE MINISTER OF LAW (SHRI GOVINDA MENON) : Sir, I am in full agreement that this is a matter which is very important; as you very rightly referred to in your ruling yesterday, the matter raised regarding the alleged discrepancy between the affidavit referred to and the statements made on behalf of the Government, is indeed a very important matter. It is for that reason that I presume that you said yesterday in your ruling that there should be a discussion. That was the ruling. But you also said that that discussion should take place sometime later, and that is on account of the *sub judice* rule which was referred to. After all, all of us in this House should be interested in preserving the rules regarding *sub judice* and it is not for nothing in the rules it has been provided that a matter which is *sub judice* should not be discussed in this House.

I said the other day that on the 1st May the discussion before the High Court of Delhi regarding this alleged discrepancy took place, and the arguments were closed on the 1st May and the court has reserved judgment. Now, in the early motion under rule 184, my friend Shri Limaye wanted a verdict of this House that this affidavit is not approved by the Parliament. I pointed out, and you accepted my point, that this is exactly the question

[Shri Govinda Menon]

which was discussed before the court, that is to say, whether the court would approve of that affidavit if in that writ case the Government should win and the court should accept the affidavit which was filed on behalf of the Government.

If in that case the petitioners should win and the court should be satisfied that discrepancies which have beee pointed out between the statements made by the Prime Minister and other Ministers and the affidavit...

MR. SPEAKER : The only point is this. We shall not touch on what the court will say. That I have already made clear. The only point is, because there is a discrepancy between the statements of the Prime Minister and the affidavit, does constitute breach of privilege ?

SHRI GOVINDA MENON : My humble submission is, it is not at all a matter of privilege. There is a writ application under article 226 of the Constitution. There is no question of setting aside the tribunal's award, because it is not under the jurisdiction of the Delhi High Court. Under article 226, the petitioners move the High Court to persuade it to issue a direction to the Government to do a certain thing or not to do a certain thing.

SHRI SHRINIBAS MISRA (Cuttack) : On a point of order, Sir. He is objecting that a matter which is *sub judice* should not be discussed. How can he make observations on the matter whether the High Court has jurisdiction or not ? It is for the Court to decide.

SHRI GOVINDA MENON : There is no prayer to set aside the tribunal's award.

Certain legal agruments were advanced before the court. For example, when an Under Secretary of the Ministry of External Affairs said...

MR. SPEAKER : I thought he has said that on behalf of the Government not in his individual capacity.

SHRI GOVINDA MENON : For the purpose of deciding this matter, it is not necessary to refer to those things. I fail to see how there can be a question of privilege. Even if there is something which the House wants to go into, I would draw your attention to rule 352 which applies to every matter. It says, a matter which is pending decision before the court should not be referred to in any speech in this House. That would mean, even a privilege motion cannot be discussed. I therefore submit that you may be pleased not to give consent to this motion. I speak on the understanding that these discussions are for enabling you to come to a conclusion whether consent should be given or not. I speak on the presumption that you are attempting to ascertain from the facts of the motion whether consent should be given or not. That is the first step. Only after you give consent, voting and other things follow. I submit that consistent with the ruling which you gave yesterday with respect to the motion under rule 184, no consent should be given. How can there be a debate in this House when rule 352 specifically says :

> "A member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending".

MR. SPEAKER : On that aspect, I am very clear. The only point is, because there is a discrepancy between the statement of the Prime Minister and the affidavit, which has been filed on behalf of Government, does it constitute privilege ?

SHRI GOVINDA MENON : All that I would submit is, this is exactly the point which was raised before the court, whether the affidavit filed by the officer concerned is weak or invalid because it is in variance with what has been stated on behalf of Government in Parliament. I submit, there have been long arguments before the court on this matter. Therefore, this will come under this. Nobody will be able to speak in this House on this motion without violating rule 352. That rule, therefore, indicates that on this motion of privilege also you should follow what you have been pleased to lay down in your ruling yesterday.

After all, assuming there is a breach of privilege, what is it that is attempted. In

a breach of privilege matter the House seeks to either censure or reprimand or punish the person who is guilty of a breach of privilege. You said yesterday that the discussion under rule 184 should await the decision of the court. In the same way there is absolutely nothing lost. Assuming there is a breach of privilege, why should it be discussed today ? A motion can be made later *(Interruptions)*. There is absolutely no use of derisive laughter in this matter. I am also entitled like any other hon. Member to put forward my point of view, which accidentally happens to be in keeping with law and what they want to say is in violation of the law. That is the only difference. Do not think that speeches and submissions made could be stopped by derisive laughter. That is of no use. That is also a breach of privilege, breach of privilege of a Member to speak in the House. I submit, therefore, Sir, that there is absolutely no breach of privilege involved and you should withhold your consent to this motion.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे ऐडमिसिबिलिटी पर सुनिये । मैं गुण दोष में नहीं जाऊंगा । आप मुझ को केवल दो मिनट के लिये सुन लीजिये ।

MR. SPEAKER : Not now. I am not giving any decision now. If I allow one or two minutes to one I will have to allow the whole house to speak for one or two minutes. I have heard both sides. The whole House cannot help me in coming to a decision. The rule clearly says that one speech from each side may be allowed and then the Chair must take a decision. I will take legal advice outside the Law Minister if necessary. As I have said, I have heard both sides and I will give my decision in the afternoon.

SHRI NATH PAI : Sir, when Shri Vajpayee moved his motion and I stood up to make my submission along with some others you said : "I will hear each one of you". The proceedings will show that.

MR. SPEAKER : Not on this issue. After it is admitted, I said, I will hear each one of you.

Here is some other important matter. Shri Nath Pai has brought to my notice that the Punjab High Court has held the prorogation of the Punjab Assembly as *ultra vires*. The Court must have given this judgment now. We have only the teleprinter message. Today being the last day of this session I would like to hear the Home Minister before we adjourn. Sometime in the evening he may give some information as to what happened, whatever information is available to him. Because, today is the last day of the session ; otherwise, I would have given him 24 hours.

13 hrs.

In the afternoon, of course, the non-official work is there. But, if necessary, we will snatch away 30 minutes or 45 minutes from non-official time so that the Home Minister may make his statement and the other items can be taken up. I hope the House will permit me to do that because, today being the last day, we will have to complete the statements etc. in the evening itself. I would request him to make his statement at about 6 or 6.30 p.m. Now, papers to be laid on the Table.

13.01½ hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Audit Report on Revenue Receipts

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) अन्तर्गत निम्नलिखित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति:-

(एक) राजस्व प्राप्तियों सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1968

(दो) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्य) 1968

[*Placed in Library. See* No. LT-1267/68].

(2) "सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों" के बारे में प्रशासन सुधार आयोग के प्रतिवेदन में की